लूट कमाई से फुरसत मिले....

पेज एक का शेष

से दस सैंपल भरे जाते हैं। यानी अधिकारी सैंपल भरने के लिए फील्ड पर निकलते हैं। अगर ऐसा है तो इन अधिकारियों को धीरज नगर और इसी तरह चलने वाली सैकड़ों फैक्ट्रियां नजर नहीं आतीं या जानबूझ कर इन्हें अनदेखा किया जाता है।

अब धीरज नगर में फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद एफएसएसएआई अधिकारी फिर से रूटीन काम में जुट गए हैं, जबकि चाहिए ये था कि अधिकारी शहर में नहीं तो कम से कम धीरज नगर और पल्ला क्षेत्र में चल रही ऐसी अनेक चाप, पनीर, छेना, रसगुल्ला, रसोई मसाले आदि बनाने वाली अन्य फैक्ट्रियों का निरीक्षण करते। सच्चाई ये है कि ऐसी फैक्ट्रियां इन अधिकारियों की देखरेख में चल रही हैं, मोटी कमाई का जरिया इन फैक्ट्रियों पर तभी तो कार्रवाई नहीं होती।

यदि सरकार वास्तव में ही जनता को मिलावटी एवं दूषित खाद्य सामग्रियों से बचाना चाहती है तो इस काम के लिए बने विभाग की मिलीभगत पकड़े जाने पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करती। बताने की जरूरत नहीं है फ्लाइंग स्कवाड के नाम पर छोटी सी पुलिस टुकड़ी जब आए दिन इस तरह के मिलावटी खाद्य उत्पादकों को पकड़ती है तो इस काम के लिए विभाग के अधिकारियों से कोई पूछताछ क्यों नहीं की जाती। इस छोटी सी टुकड़ी द्वारा पकड़े जाने का अर्थ यह समझा जा सकता है कि संबंधित विभाग वालों की मिलीभगत से ही मिलावट का काला धंधा चल रहा है।

नगर निगम का सफाई कर्मी....

खुद ही गायब कर दी है। अकाउंट या एचआर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को बता दिया जाता है कि फाइल निगमायुक्त के पास है, इसके बाद वे फाइल मांगने की हिम्मत नहीं करते।

पुस्तकालय अनुचर होने के बावजूद प्रेमचंद निगमायुक्त कार्यालय में तैनात सभी कर्मचारियों, लिपिकों से ऊपर बताया जाता है। कहने को तो निगमायुक्त के पीए का कोई पद नहीं है लेकिन निगम के अधिकारी कर्मचारी ही नहीं निगमायुक्त से मिलने आने वाले ठेकेदार, अधिकारी भी प्रेमचंद को पीए ही जानते- मानते हैं। वजह यह है कि निगमायुक्त की मेज पर पहुंचने और वहां से निकलने वाली प्रत्येक फाइल प्रेमचंद की मेज से होकर ही गुजरती है। अधिकारियों से इतनी अच्छी सांठ-गांठ है कि चपरासी होने के बावजूद नगर निगम के आला अधिकारियों को सरकार की तरफ से मिलने वाले बंगले में रह रहा है।

बेताज बादशाह बने इस अनुचर की तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में इतनी दहशत है कि उसके फरमान को निगमायुक्त का ही फरमान माना जाता है। निगम के भरोसेमंद सूत्र बताते हैं कि जेई आदि को मनपसंद स्थान पर पोस्टिंग दिलाने के लिए अधिकारियों को खुश करने का सुविधा शुल्क प्रेमचंद ही वसूल करता है। ठेका देने से लेकर विकास कार्यों की स्वीकृति, भुगतान आदि सभी फाइलें निगमायुक्त के बाद पहले प्रेमचंद तक ही पहुंचती हैं, इसलिए इनका कमीशन या सुविधा शुल्क वसूलने का काम भी वही करता है।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को इतना बड़ा ओहदा दिए जाने से निगमायुक्त कार्यालय के लिपिकों से लेकर वरिष्ठ कर्मचारियों में रोष है लेकिन साहब की चाहत होने के कारण कोई खुल कर शिकायत नहीं करता। खास बात यह है कि प्रेमचंद की पहुंच कांग्रेस से लेकर भाजपा सरकार में भी अच्छी है यही कारण है कि कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा का करीबी होने के बावजूद भाजपा सरकार के नौ साल के कार्यकाल में वह अनुचर रहते हुए भी निगमायुक्त के कथित निजी सहायक पद पर बना हुआ है। जीरो टालरेंस के दावे करने वाले मुख्यमंत्री खट्टर को जब निगम के बड़े घोटाले नहीं नजर आते तो एक अदना से कथित पीए का भ्रष्टाचार कहां दिखेगा। अब देखना है कि नव नियुक्त निगमायुक्त मोना ए श्रीनिवास उसे पुन: सफाई कर्मचारी पर वापस भेजेंगी।

मोदी के भाषण पर स्वास्थ्य विभाग ने खर्चे 19 करोड़ 66 लाख

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

दिनांक एक जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल शहडोल का दौरा किया। उनके लिए घेर घोट कर बसों में लादकर आदिवासियों को लाया गया था। मोदी उनको यह बताने आए थे कि उन्हें उनके स्वास्थ्य की कितनी गहरी चिंता है तथा बीमारी की स्थिति में उनको क्या-क्या करना चाहिए। अब चूंकि कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग की ओर से था इसलिए मंच बनाने व सजाने, बैनर होर्डिंग लगाने तथा वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराने पर स्वास्थ्य विभाग ने 19 करोड़ 66 लाख रुपये खर्च कर दिए। वह बात अलग है कि वास्तव में कितने खर्च हुए और कितने विभिन्न लोगों द्वारा डकारे गए लेकिन स्वास्थ्य विभाग के बजट से तो यह रकम काफ़ूर हो ही गई।

उक्त खर्चा तो केवल सभास्थल तक का ही है। इसमें वह खर्चा शामिल नहीं है जो आदिवासियों को बहला-फुसला कर खाना-पीना खिलाने आदि पर खर्च किया गया था। इसमें वह खर्चा भी शामिल नहीं है जो उनके आगमन पर हजारों पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाने पर खर्च किया जाता है। उस खर्चे की तो बात ही न की जाए जिस शहंशाही हवाई जहाज में बैठ कर वे उड़ते हैं और फिर सभास्थल पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाता है। इन हेलीकॉप्टरों के लिए तीन हेलीपैड भी बनाए गए थे। प्रचार-प्रसार में कोई कमी न रह जाए इसके लिए अनेकों स्थानीय व राष्ट्रीय अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापनों पर जो खर्च किया गया वह तो न्यारा है ही। यह तमाम खर्चे उसी भूखी नंगी जनता के टैक्स से ही वसूला जाता है जिनके पास खाने को रोटी नहीं है। जब टैक्स से भी पूरा नहीं पड़ता तो राज्य सरकार बड़े पैमाने पर कर्ज लेकर इस तरह की अय्याशी करती है। फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार पर तीन लाख 32 हजार करोड़ से अधिक का कर्जा है।

आज़ाद नगर में चोरी और सीनाजोरी पुलिस मज़दूर को झूठा क्यों समझती है?

क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा

आज़ाद नगर की झुग्गी संख्या 1916 में 40 वर्षीय सुरेन्द्र कुमार अपने परिवार के साथ रहते हैं। अगले हिस्से में जिसका दरवाज़ा गली को ओर खुलता है वहां उन्होंने अपनी किराना व जनरल स्टोर की दुकान बना ली है। छत सीमेंट की चद्दरों वाली है। उनकी दुकान के सभी ग्राहक, बस्ती में आस-पास रहने वाले ग़रीब मज़दूर ही हैं, जो दैनंदिन ज़रूरत का सामान उधार लेते रहते हैं, और महीने की 10 तारीख के बाद, वेतन मिलते ही महीने भर के खर्च का भुगतान करते हं। महीने की 16-17 तारीख तक, उधारी का पैसा वापस मिल जाता है। तब, वे उस थोक दुकानदार का भुगतान कर देते हैं, जिससे माल ख़रीदते हैं। उनके गल्ले में, हर महीने की 17 तारीख को सबसे ज्यादा पैसा होता है, यह बात मोहल्ले में सभी को मालूम है।

17 अगस्त की रात, सुरेंद्र जी के घर चोरी हो गई। चूंकि, दुकान समाप्त होते ही, घर शुरू हो जाता है, सुरेन्द्र कुमार वहीँ सोए हुए थे। चोरों ने सीमेंट की चद्दर हटाई और गल्ले से पैसे निकाल लिए। थोड़ी आहट हुई, उन्हें लगा छत पर बिल्ली होगी लेकिन तब ही याद आया, कि गल्ले में उनकी महीने भर की बिक्री का पैसा है। वे उठे और जैसे ही गल्ला ख़ाली नज़र आया, उनकी चीख निकल गई, 'हाय मैं लुट गया। चोर मेरे 70,000 ले गए। उनकी पत्नी और भाई भी जाग गए। उसी वक़्त, रात के लगभग 2 बजे बस्ती में कुछ दूरी से एक और शोर सुनाई दिया। शोर-शराबे से पूरा मोहल्ला इकठ्ठा हो गया। पता चला कि सुरेन्द्र कुमार के घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर, बबुंति नाम की जो मज़दूर महिला रहती हैं उनकी झुग्गी में भी चोर घुसा और उनका मोबाइल उठाकर जैसे ही चला, उनकी आंख खुल गई। वे चोर को पहचान गईं। वही मूसा, पिता का नाम अमीन, नाम का लफंगा युवक था जो बस्ती में ही रहता है और मेहनत कर खाने की बजाए, चोरी-चकारी, नशा खोरी करने के लिए कुख्यात है। इतना ही नहीं वह, इसी किस्म के आवारा लुम्पन युवकों का मुखिया भी बना फिरता है और बस्ती के ग़रीब मज़दूरों को धमकाता भी रहता है। बबुंति उसके पीछे, उसके घर तक भागीं, लेकिन तब ही मूसा ने धमकी दी, 'पीछे हट जा वर्ना मार डालूंगा'। वे लौट आईं।

सुरेन्द्र कुमार के घर के साथ वाली झुग्गी नंबर 1917 में 'क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा' का दफ़्तर है, जहां संगठन के अध्यक्ष कॉमरेड नरेश, अपने परिवार के साथ रहते हैं। इस एरिया के अधिकतर मज़दूर इस संगठन के सदस्य हैं। 17-18 की रात 2.00 बजे बस्ती के लगभग सारे लोग इकट्ठे हो गए और 112 नंबर डायल किया गया। पुलिस जल्दी ही, घटना-स्थल पर पहुँच गई। पुलिस ने तस्वीरें लीं, पीड़ितों और इकठ्ठा हुए अन्य लोगों से बात की। उन्होंने सलाह दी कि आप लोग मुजेसर थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाइए। लगभग 60 लोग, उसी वक़्त मुजेसर थाना पहुंचे। वहां मौजूद पुलिस सिपाही ने यह कहकर लौटा दिया कि सुबह नौ बजे के बाद आना। 18 अगस्त को, सुबह 10 बजे लगभग 60 लोगों के साथ दोनों चोरी- पीड़ित फिर से थाने पहुंचे। पूरी घटना का सारा ब्यौरा पुलिस को बताया। उसके बाद, अपराध जाँच एजेंसी (CIA) की टीम मौक़ा-ए-वारदात पर पहुंची। उनकी तहकीक़ात काबिल-ए-गौर है। महीने भर की अपनी बिक्री खो चुके, सुबकते सुरेन्द्र कुमार से पुलिसिया अंदाज़ में पहला सवाल पूछा जाता है, "तेरे पास 70,000 रुपये, आए कहां से बहन...द, ये बता? झूठ बोलता है, स्साले। ये, ऐसे नहीं बताएगा इसे थाने ले चलो'। सुरेन्द्र डर से कांपने लगे और उनकी पत्नी दहाड़ें मारकर रोने लगीं। पुलिस के इस व्यवहार को बस्ती के सभी लोग जानते हैं। इसका असल मतलब होता है, पुलिस रिपोर्ट करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई!!

सुरेन्द्र कुमार यह भी कहते रहे कि वे उन लोगों के नाम भी बता सकते हैं, जिन्होंने अपनी उधारी चुकाई। उन्होंने उस थोक व्यापारी का नाम-पता भी बताया जिसके पैसे उन्हें लौटाने थे। फिर भी पुलिस वाले बोलते रहे, 'देख तू, झूठ मत बोल। हमें सच उगलवाना भी आता है!!!' कारखाना मालिक, अमीर लोग, जब चोरी की शिकायत करते हैं तब भी क्या पुलिस इसी तरह जांच शुरू करती है? हर मज़दूर झूठा है और हर अमीर सत्यवादी हरिश्चंद है, पुलिस ऐसा क्यों सोचती है? लोग कह रहे हैं कि एफआईआर भी क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा द्वारा मामले की दख़ल लेने की वजह से ही दर्ज हुई, वर्ना उन्हें वैसे ही डराकर भगा दिया गया होता।

उसके बाद, उन्होंने 'क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा' से संपर्क कर, पुलिस के इस रवैय्ये की शिकायत की और बताया कि पुलिस वाले तो हमें ही बंद करने की धमकी दे रहे है। उसके बाद, क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा की स्थानीय टीम घटनास्थल पर पहुंची और सभी 60 लोगों के साथ मुजेसर थाने में भी गई। मुझेसर थाने के एसएचओ, कबूल सिंह ने क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा के अध्यक्ष नरेश को भरोसा दिलाया कि जांच में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बाक़ायदा एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसकी कॉपी दोपहर बाद आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 380 में दज एफआईआर 0510/ 18.08.2023, 9:40 एएम की प्रति उसी दिन 4 बजे हमें प्राप्त हो गई। जांच अधिकारी का नाम एएसआई संजीत सिंह है।

बस्ती के छटे हुए अपराधी मूसा का नाम बार-बार बताए जाने के बावजूद भी, एफआईआर में नहीं है। 'अज्ञात चोरों की तलाश की जाए', इसकी जगह आरोपी मूसा का नाम होना चाहिए था। हालांकि, सीआईए की टीम मूसा को उसी दिन, उठाकर ले गई लेकिन 3 घंटे बाद ही उसे छोड़ दिया गया। वह उसी तड़ी स बबंती के घर के सामने से, धमकी देता घूम रहा है। इतना ही नहीं, उसका साथी गुड्डू, 23 अगस्त को नशे की हालत में सुरेन्द्र कुमार की दुकान पर पहुंचा और बोला, "अच्छा तो तुम्हारी दुकान में चोरी हो गई। काफ़ी नुकसान हो गया। पैसे तो वापस मिल जाने चाहिए। आप कहो तो मैं मूसा भाई से बात करूं।" सुरेन्द्र कुमार ने इस जानकारी को पुलिस को देने के लिए संजीत सिंह को फोन किया लेकिन उन्होंने पूरी बात भी नहीं सुनी और बोले 'तुम सीआईए से बात करो'। पीड़ितों को मुजेसर पुलिस और सीआईए के बीच झुलाया जा रहा है। सभी जानते हैं कि चोरी के मामले में अपराधियों को पकड़ने में जितनी देर होती है चोरी के माल के पकड़े जाने की संभावना उतनी ही कम होती जाती है। क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा, पुलिस से मांग करता है कि,

1) मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। क़ुसूरवार को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। अदालत उसे उसके अपराध की सजा दे, पुलिस इस बाबत अपना फ़र्ज़ निभाए। हमारा संगठन, पुलिस जांच में दख़ल नहीं देगा। चोर को बचाने हम कभी नहीं जाएंगे लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक (24 अगस्त सुबह 11 बजे) कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई है। सुरेन्द्र कुमार को उनका चोरी गया पैसा और बबंती जी को उनका मोबाइल वापस नहीं मिला है। कृपया इंसाफ दिलाइये। हम इंसाफ की गुहार लगाते रहेंगे और चोरी गया माल वापस पीड़ितों को मिलने तक हम इस फ़ाइल को बंद नहीं होने देंगे।

2) आज़ाद नगर बस्ती में भी नशे का आपराधिक कारोबार ख़ूब फल-फूल रहा है। पुलिस शिद्दत से जांच करे तो गुनहगारों को पकड़ना मुश्किल नहीं। नशे के धंधे में भी यही मूसा लिप्त है, आज़ाद नगर बस्ती में ये चर्चा आम है। युवाओं को नशे के गर्त में धकेल रहे अपराधियों को उनके आकाओं समेत गिरफ्तार कीजिए। नशे और अपराध के बीच सीधा संबंध है। कृपया अपराधियों पर सख्ती कीजिए।